भारत-यूरोपीय यूनियन का संयुक्त बयान

अक्तूबर 13, 2006
हलेसिंकी, फिन्लैंड

1. सातवां यूरोपीय यूनियन-भारत शिखर सम्मेलन 13 अक्तूबर, 2006 को हेलसिंकी में हुआ। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री मट्टी वेनहेनन ने यूरोपीय यूनियन का प्रतिनिधित्व किया और उनके साथ उनके विदेशी और सुरक्षा नीति के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि, डा0 जेवियर सोलाना और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष श्री जोस मैनुअल बारोसो, विदेशी संबंधों की यूरोपीय कमीश्नर श्रीमती बेनिटा फेरेरो - वाल्डनर और यूरोपीय व्यापार कमीश्नर श्री पीटर मन्डेलसन,फिनलैंड के विदेश मंत्री श्री इरिक्की टयोमियोजा और फिनलैंड की विदेश व्यापार और विकास मंत्री श्रीमती पोला लेटोमाकी थे। भारत के गणतंत्र का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह, श्री कमल नाथ, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री आनन्द शर्मा, विदेश राज्य मंत्री और श्री एम.के. नारायणन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने किया। इन नेताओं ने निम्नलिखित संदेश दियाः

2. यूरोपीय यूनियन-भारत, विश्व के दो बड़े लोकतंत्र और बहुध्रुवीय विश्व में विश्व स्तरीय कार्यकर्त्ता होने के कारण हेग में पाँचवे यूरोपीय यूनियन-भारत शिखर सम्मेलन में किए गए सामरिक समझौते में दिए गए वचनों को दोहराते हैं। यह समझौता लोकतंत्र, बहुलवाद, विधि के नियम के साझा मूल्यों और मानवाधिकार के सम्मान पर आधारित है। नई दिल्ली में हुए छठे यूरोपीय यूनियन-भारत शिखर सम्मेलन में व्यापक और दूरदर्शी संयुक्त कार्य योजना में इन दोनों पहलुओं को शामिल किया गया। तब से यूरोपीय यूनियन-भारत द्विपक्षीय और विश्व स्तर पर अपने सामरिक समझौते को तैयार करने और उसे लागू करने के लिए साथ-साथ काम कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने संयुक्त कार्य योजना के क्रियान्वयन में हुई प्रगति का स्वागत किया और इस नीति को आगे बढ़ाने की अपनी वचनबद्धता के प्रति पुनः निष्ठा प्रकट की।

3. नेताओं ने सामरिक समझौते के साझीदारों के बीच गंभीर और सार्थक बातचीत का स्वागत किया। भारत और यूरोपीय यूनियन के प्रत्येक सदस्य देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता में सुधार भी हुआ है। नया परामर्शदायी तंत्र बनाने के लिए व्यावहारिक कदम उठाए गए हैं। इसके लिए अनेक बार सरकारी दौरे किए गए हैं। इससे इस विषय के सभी देशों के विशेषज्ञों के बीच कार्य के स्तर पर औपचारिक और अनौपचारिक तौर पर दैनिक संपर्कों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यूरोपीय यूनियन-भारत के बीच भारत और यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों के बीच कारोबारियों, प्रोफेशनल व्यक्तियों और पर्यटकों तथा अनुसंधानकर्त्ताओं, वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों और शिक्षाविदों के आने-जाने को सरल बनाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों के माध्यम से सहयोग बढ़ा है।

4. यूरोपीय यूनियन-भारत ने नियमानुसार द्विपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए वायदा किया है। दोहा विकास कार्यसूची (डी डी ए) में बहुपक्षीय व्यापार वार्ता का सफल परिणाम उनकी व्यापार नीति को दी जाने वाली सबसे पहली प्राथमिकता रही और वे यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत हो गए थे कि द्विपक्षीय व्यापार संबंधों की प्रगाढ़ता से बहुपक्षीय व्यापार क्षेत्र का विस्तार करने में सहायता मिलेगी।

5. यूरोपीय यूनियन-भारत के बीच दो तरफा व्यापार और निवेश में हुई तेज गति से हुई वृद्धि से द्विपक्षीय समझौतों की सुदृढ़ता दिखाई दी। दोनों ओर के नेताओं ने व्यापार और निवेश संपर्क को विस्तृत

करने और मजबूत करने को प्रोत्साहित किया। इस बात को स्वीकार करते हुए कि मजबूत आर्थिक संबंध एक दूसरे के लिए लाभदायक हैं और इससे सामरिक साझेदारी को समर्थन मिलेगा इन नेताओं ने अपने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इस शिखर सम्मेलन ने उच्च स्तरीय व्यापार समूह द्वारा किए गए कार्य की सराहना की और भावी व्यापक आधार वाले व्यापार और निवेश करार के लिए इस मामले का समर्थन किया। शिखर सम्मेलन में इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि दोनों पक्षों को इस करार पर बातचीत आगे बढ़ानी है।

6. यूरोपीय यूनियन-भारत सहयोग में उद्योग और व्यापार की अधिक भागीदारिता और दोनों पक्षों के कारोबार के बीच बातचीत व्यापार और निवेश को बढ़ाने के समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। यूरोपीय यूनियन - भारत व्यापार शिखर वार्ता और यूरोपीय यूनियन-भारत सी ई ओ गोलमेज का आरम्भ कल हेलसिंकी में हुआ था जिसमें दोनों ओर के बड़े व्यापारी नेताओं के बीच उपयोगी और सार्थक बातचीत हुई।

7. यूरोपीय यूनियन-भारत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाने और आर्थिक प्रगति, समृद्धि और सतत विकास करने के लिए एक साथ कार्य करने और सुशासन लागू करने के लिए वचनबद्ध है। यूरोपीय यूनियन-भारत दोनों मानवाधिकार और मूलभूत आजादी का समर्थन करने के लिए वचनबद्ध है। समानता और सम्मान की भावना से दोनों पक्षों की मानवाधिकार पर बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बातचीत जारी रहेगी।

8. नेताओं ने हाल ही में हुई यूरोपीय यूनियन-भारत के बीच सुरक्षा पर मई 2006 में पहली बार हुई बातचीत का स्वागत किया और इसे वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों तथा निःशस्त्रीकरण और अप्रसार तथा समान समस्याओं के द्विपक्षीय मामलों पर विचारों के गंभीर आदान-प्रदान के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण मंच बताया।

9. प्रभावी देशों के संगठन की आवश्यकता और नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति अपनी वचनबद्धता पर जोर देते हुए नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में सहयोग को बढ़ाने और वैश्विक सरोकार और विकास तथा पर्यावरण के मामलों पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी बात कहने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। इस शिखर सम्मेलन में दृढ़,प्रभावी और दक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्व को रेखांकित किया गया और नेताओं ने व्यापक संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की आवश्यकता को भी स्वीकार किया। इस शिखर सम्मेलन में नई स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और पीस बिल्डिंग कमीशन की भूमिका को सुदृढ़ बनाने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने पर सहमति जताई गई और संयुक्त राष्ट्र को आज के विश्व की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के प्रयासों पर लगातार बल देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसी संदर्भ में नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में अधिक कुशल पर्यावरण कार्यकर्त्ताओं के होने की आवश्यकता पर जोर दिया। वे मौजूदा संस्थाओं पर अपेक्षाकृत अधिक संगत संस्थागत फ्रेमवर्क तैयार करने की संभावनाओं का पता लगाते रहने पर भी सहमत हो गए। शिखर सम्मेलन के नेताओं ने गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए दंड देने की आवश्यकता पर अपनी सहमति भी अभिव्यक्त की।

10. यूरोपीय यूनियन-भारत ने निःशस्त्रीकरण के लिए और डब्ल्यू एम डी और उनकी वितरण प्रणाली के प्रसार का प्रतिकार करने के लिए एक साथ काम करने के अपने साझा हितों की पुष्टि की। वे इस बात को समझते हैं कि अत्यन्त विध्वंसकारी हथियारों का प्रसार और उनकी वितरण प्रणाली तथा

आंतकवादियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथ इन हथियारों के लग जाने का जोखिम अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इस संदर्भ में उन्होंने राष्ट्रीय क्रियान्वयन और यू एन एस सी (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) संकल्प 1540 के जरिए सभी राष्ट्रों द्वारा अपनी मौजूदा बाध्यताओं के बावजूद इसके पूर्ण अनुपालन के महत्व पर जोर दिया। वे इस बात से सहमत थे कि शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए सहयोग देते हुए दो रूपों में इस्तेमाल किए जाने वाले माल के लिए प्रभावकारी राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण उपाय हथियारों के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

11. इन नेताओं ने कोरिया गणराज्य द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता का उल्लंघन करते हुए परमाणु परीक्षण करने पर गहरी चिन्ता व्यक्त की। वे इस बात से सहमत थे कि इस परीक्षण से क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को खतरा है और उन्होंने इनके प्रसार को रोकने पर विशेष बल दिया। नेताओं ने कोरिया गणराज्य से अनुरोध किया कि वह बिना शर्त छः पक्षीय वार्ता करने के लिए तैयार हो जाए।

12. नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मध्य पूर्व/पश्चिमी एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से एक व्यापक शांति योजना तैयार करने पर जोर दिया है। उन्होंने मौजूदा समझौते और संगत यू एन एस सी संकल्प, रोडमैप और अरब लीग संकल्प (बेरूत 2002) के आधार पर इजरायल और फिलस्तीनी विवाद का बातचीत के जरिए हल निकालने की बात पुनः कही है। इन नेताओं ने लेबनान की स्थिति पर भी विचार विमर्श किया और यू एन एस सी संकल्प 1701 लागू करने का समर्थन किया। उन्होंने यू एन आई एफ आई एल को सुदृढ़ बनाने का भी स्वागत किया जिसके लिए यूरोपीय यूनियन के सदस्य तथा भारत जैसे सदस्यों ने अर्ध सैन्य बल में अपना योगदान दिया और साथ ही ये देश दो दशक से अधिक समय पहले से अर्थात् इसके आरम्भ से यू एन आई एफ आई एल में योगदान दे रहे हैं, उन्होंने लेबनान के लोगों को उनके देश के पुनर्निर्माण के लिए मानवीय आधार पर सहायता प्रदान करने और पुनरूद्धार के लिए मदद देने के अपने निश्चय पर भी बल दिया।

13. इसके अतिरिक्त अन्य बातों के साथ-साथ नेताओं ने सूडान और ईरान के परमाणु कार्यक्रम की स्थिति पर भी विचार - विमर्श किया। उन्होंने बर्मा/म्यांमार की स्थिति पर भी विचार - विमर्श किया और इस बात पर भी सहमति जताई कि बर्मा/म्यांमार में लोकतंत्र बहाली की दिशा में हुई प्रगति और राष्ट्रीय समस्या का हल निकालने से इन देशों में शांति और समृद्धि आएगी।

14. यूरोपीय यूनियन-भारत ने अफगानिस्तान में स्थिरता और उसके पुनर्निर्माण में अफगान सरकार को सहायता देने की अपनी दीर्घकालिक वचनबद्धता को पुनः दोहराया। इस संदर्भ में दोनों पक्षों ने 18-19नम्बर 2006 को नई दिल्ली में होने वाले दूसरे क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सम्मलेन का स्वागत किया। उन्होंने टिप्पणी की कि यद्यपि हाल ही के वर्षों में काफी सफलताएँ हासिल की गई हैं फिर भी सुरक्षा,शासन, कानून, आर्थिक और सामाजिक विकास और मानवाधिकार के क्षेत्र में अब भी कठिन चुनौतियाँ सामने हैं। उन्होंने अफगान सरकार को पूरे देश को नियंत्रित करने और चल रहे विद्रोह को दबाने के लिए निरन्तर सहायता देने की बात याद दिलाई। इस संदर्भ में नशीले पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करने के प्रयासों पर जोर दिया गया।

15. नेताओं ने नेपाल में प्रजातंत्र की बहाली का स्वागत किया। इससे देश के सामने आई चुनौतियों का शांतिपूर्ण समाधान ढूँढने का रास्ता निकला है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं ने हिंसा

रहित वातावरण में राजनीतिक स्थिरता पुनः प्राप्त करने के लिए सभी राजनीतिक समूहों(दलों) के बीच बातचीत का स्वागत किया। उन्होंने नेपाल में बहुपक्षीय लोकतंत्र के संदर्भ में कानून और मानवाधिकार को सम्मान देने संबंधी दोनों के सामंजस्य के महत्व पर बल दिया।

16. दोनों पक्ष इस बात के कायल हैं कि हिंसा श्रीलंका की समस्या का हल नहीं है और उन्होंने सभी दलों से तत्काल बातचीत पुनः आरम्भ करने का आह्वान किया। वर्तमान विरोध से देश को बहुत नुकसान हुआ है जिसमें जीवन की हानि, हजारों की संख्या में आंतरिक विस्थापन और विस्थापितों का भारत की ओर कूच करना शामिल है। नेताओं ने श्रीलंका में शांति लाने के प्रयासकर्त्ता के रूप में नार्वे द्वारा किए जा रहे प्रयासों का सतत् समर्थन करने की बात कही।

17. यूरोपीय यूनियन ने भारत द्वारा सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ) में आब्जर्वर की हैसियत से यूरोपीय यूनियन को लाने के समर्थन की सराहना की जिस पर पहली-दूसरी अगस्त 2006 में ढाका में 27वें मंत्रि-परिषद में विचार किया गया और उसका अनुमोदन किया गया। यूरोपीय यूनियन अप्रैल पहली से चार अप्रैल,2007 तक नई दिल्ली में होने वाले 14वें सार्क शिखर सम्मेलन में आब्जर्वर के रूप में भाग लेने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है।

18. नेताओं ने 11 सितम्बर,2006 को हेलिंस्की में हुए छठे ए एस ई एम शिखर सम्मेलन में ए एस ई एम के विस्तार (एशिया यूरोप बैठक) के निर्णय का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये सभी नेता ए एस ई एम प्रक्रिया में भारत के भावी योगदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि इसने दूसरे दशक में प्रवेश किया है। उन्होंने यह टिप्पणी भी की कि भारत के योगदान से ए एस ई एम की प्रक्रिया को प्रतिनिधित्व, गति और नवीन सोच मिलेगी क्योंकि ए एस ई एम एशिया और यूरोप के बीच बातचीत और सहयोग का मुख्य मंच है।

19. यूरोपीय यूनियन-भारत आतंकवाद की गंभीर समस्या से निपटने के लिए एकजुट हो गए हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद सर्वाधिक गंभीर संकट बन गया है। यूरोपीय यूनियन-भारत ने हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा की है चाहे वह किसी के द्वारा, कहीं भी और किसी भी प्रयोजन के लिए फैलाया गया है। आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई केवल तभी सफल हो सकती है जब इस लड़ाई को निरन्तर और व्यापक स्तर पर लड़ा जाए। इसलिए यूरोपीय यूनियन और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के फ्रेमवर्क में आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में सहयोग देने को विशेष महत्व दिया और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी अधिवेशनों और उससे संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए और विश्व स्तर पर इसका समर्थन करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। यूरोपीय यूनियन-भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर विशाल अधिवेशन को अंतिम रूप दिए जाने के लिए सक्रिय रूप से काम करते रहेंगे। उन्होंने 8 सितम्बर 2006 को जनरल असेम्बली में पहली संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी नीति को अंगीकार करने का स्वागत किया। यूरोपीय यूनियन-भारत ने इस नीति के पूर्ण क्रियान्वयन को समर्थन देने का वचन दिया। नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय विधि, विशेष तौर पर मानवाधिकार कानून, विस्थापितों के लिए कानून अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून की बाध्यताओं को पूरा सम्मान देते हुए आतंकवाद का सफाया करने के वचन को पुनः दोहराया। दोनों पक्ष आतंकवाद विरोध पर सहयोग देते रहने के लिए प्रतिबद्ध हुए और उन्होंने 2006 में अगले नियमित परामर्शदायी सम्मेलन को उत्साह की नजर से देखा। यूरोपीय यूनियन-

भारत की सामरिक साझेदारी के प्राथमिक क्षेत्रों में से एक क्षेत्र आतंकवाद कोदूर करने के लिए दिए जाने वाले सहयोग को मजबूत बनाना है।

20. यूरोपीय यूनियन-भारत दोनों ने स्थायी और सतत विकास के मूल मुद्दे के रूप में ऊर्जा की निश्चित उपलब्धता को उच्च प्राथमिकता दी। यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच इस समय और भावी नीति पर होने वाली बातचीत और व्यावहारिक सहयोग का प्रमुख विषय ऊर्जा है। यूरोपीय यूनियन-भारत ऊर्जा व्यापार सम्मेलन विभिन्न ऊर्जा उत्पादकों को इस प्रक्रिया में एक साथ लाने का महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने चौथे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कार्यकारी समूह की स्थापना पर भी संतोष व्यक्त किया। यूरोपीय यूनियन-भारत प्रदूषण रहित कोयला प्रौद्योगिकी और सतत प्रदूषण रहित ऊर्जा के प्रयोग के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने और विशेषज्ञ तैयार करने का कार्य निरंतर करते रहेंगे।

21. इन नेताओं ने इस बात का फिर समर्थन किया कि सभी देशों को अपने-अपने समान और अलग-अलग उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं के अनुसार मौसमगत परिर्वतनों के अनुसार तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने यूरोपीय यूनियन-भारत द्वारा प्रदूषण रहित विकास और मौसमी परिवर्तनों के संबंध में उठाए गए कदमों को लागू करने में हुई प्रगति का स्वागत किया। उन्होंने मुख्य मामलों पर बातचीत जारी रखने और विचारों के आदान-प्रदान पर भी सहमति व्यक्त की, विशेष स्प से मांट्रियल कार्य योजना के अंतर्गत आरम्भ की गई प्रक्रियाओं से संबंधित मामलों पर। उन्होंने संयुक्त रूप से टिकाऊ और दक्ष ऊर्जा प्रणाली के विकास, अंतरण,प्रतिष्ठापन और प्रसार को सरल बनाने, दुबारा प्रयोग किए जा सकने वाले ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने, कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा दक्षता,क्योटोद (ky0t0) प्रोटोकॉल प्रणाली लागू करने के प्रति संयुक्त रूप से प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने मौसमी परिवर्तनों के कारणों और उनके दुष्प्रभाव को बताने के लिए उपभोग और उत्पादन के सुनिश्चित पैटर्न को प्रोत्साहित और संवर्धित करने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने विशेष तौर पर ऊर्जा के निश्चित उत्पादन को बढ़ाने, सतत ऊर्जा आपूर्ति, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की नयी प्रणाली आरम्भ करने और इस उत्सर्जन में कमी लाने की क्रियाओं को साथ-साथ अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि भविष्य में कम कार्बन उत्सर्जन वाला वातावरण बन सकें।

22. यूरोपीय यूनियन-भारत ने अपनी-अपनी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाओं और भविष्य में संयुक्त अनुसंधान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को सुदृढ़ करने के पारस्परिक लाभों को प्राप्त करने के प्रयासों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। नेताओं की आशा 2007 में यूरोपीय यूनियन - भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करार के नवीकरण पर टिकी हैं। दोनों पक्षों ने आई टी ई आर प्रोजेक्ट में भारत की पूर्ण सदस्यता का स्वागत किया।

23. यूरोपीय यूनियन-भारत के बीच दो तरफा व्यापार, पर्यटन, अनुसंधान और विद्यार्थियों के आवागमन और व्यापार (कारोबार) में स्वस्थ वृद्धि और संभावना को देखते हुए नेताओं ने परिवहन व्यवस्था की मजबूती के महत्व को स्वीकार किया ताकि एक देश से दूसरे देश में आने जाने को बढ़ावा मिल सके और उसे सरल बनाया जा सके। नेताओं ने 2006 में नागर विमानन सहयोग के क्षेत्र में हुई प्रगति की सराहना की और विमानन क्षेत्र में भविष्य में सहयोग को बढ़ाने की प्रबल संभावनाओं को दोहराया । नेताओं ने नई दिल्ली में 23-24 नवम्बर,2006 को होने वाले पहले यूरोपीय यूनियन-भारत विमानन शिखर सम्मेलन के संयुक्त संगठन का स्वागत किया और यूरोपीय यूनियन-भारत के बीच समस्तरीय करार और नई तकनीक

सहयोग कार्यक्रम की प्राथमिकताओं के संबंध में करार को अंतिम रूप देने की संभावनाओं का स्वागत किया।

24. नेताओं ने यूरोपीय यूनियन-भारत के बीच समुद्री परिवहन करार के लिए बातचीत आरम्भ करने का स्वागत किया और इस बात का परिणाम परस्पर लाभकारी करार के रूप में लाने के दृष्टिकोण से बातचीत की प्रक्रिया जारी रखने को अपना पूरा समर्थन दिया।

25. नेताओं ने रोजगार और सामाजिक नीति पर यूरोपीय - यूनियन और भारत के बीच बातचीत और सहयोग पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिए जाने का स्वागत किया और आशा की कि इस समझौते पर बहुत जल्दी हस्ताक्षर हो जाएँगे।

26. नेताओं ने आपसी हितों के क्षेत्र में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को और अधिक बढ़ाने और नई नीति स्थापित करने के लिए बातचीत करने की अपनी वचनबद्धता का पुनः समर्थन किया। उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स और जैव प्रौद्योगिकी विशेष तौर पर आयुर्वेद के संबंध में (भारतीय परम्परागत औषध प्रणाली) और डाटा प्रोटेक्शन और नई प्रणालियों के विकास के संबंध में कार्यकारी समूह की पहली बैठक की सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आयुर्वेद प्रणाली का अध्ययन करने के लिए यूरोपीय कमीशन से विशेषज्ञों का एक दल इस वर्ष भारत का दौरा करेगा।

27. यूरोपीय यूनियन-भारत के आर्थिक सहयोग के व्यापक संदर्भ में नेताओं ने नियमित समष्टिगत अर्थव्यवस्था संबंधी बातचीत का समर्थन किया जिससे दोनों पक्ष अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास और नीतिगत चुनौतियों पर विचार-विमर्श कर सकेंगे साथ ही विश्व की अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों पर भी विचार-विमर्श कर सकेंगे। दोनों पक्षों ने अपनी वित्तीय सेवा नियामक बातचीत को जारी रखने के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई। बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन को पोषित करने में निकट सहयोग के लाभों को स्वीकार करते हुए नेताओं ने इस विषय पर सक्रिय बातचीत करने तथा क्षमता निर्माण क्रियाकलापों में सहयोग करने, मानव संसाधन विकास और जन चेतना कार्यक्रमों को तैयार करने के प्रति अपनी वचनबद्धता का फिर समर्थन किया।

28. सांस्कृतिक संबंधों पर यूरोपीय - यूनियन और भारत की संयुक्त घोषणा 2004 का हवाला देते हुए दोनों पक्षों ने सांस्कृतिक वैविध्य और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की विभिन्नता के संरक्षण और संवर्धन पर यूनेस्को समझौते के समर्थन और क्रियान्वयन और नए युग में संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच बातचीत को बढ़ाने के महत्व पर बल दिया।

29. दोनों पक्षों ने नई दिल्ली में नवम्बर 2006 में आयोजित किए जाने वाले पहले यूरोपीय यूनियन-भारत उच्च शिक्षा मेले का स्वागत किया।

30. नेताओं ने यूरोपीय यूनियन-भारत सिविल-सोसायटी राउन्ड टेबल के कार्य के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और यूरोपीय यूनियन-भारत के संबंधों के लिए सिविल सोसायटी के मूल्यवान योगदान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने यूरोपीय यूनियन-भारत सिविल सोसायटी इन्टरनेट फोरम आरम्भ करने का स्वागत किया।

* * * * * * *